ALL INDIA BANK OF MAHARASHTRA EMPLOYEES FEDERATION
(Affiliated To All India Bank Employees Association)
Website: www.aibomef.com e-mail: aibomef2014@gmail.com

परिपत्र संख्या- 14/2022 **30 दिसंबर ,2022**

शुरू हुआ है जंग हमारा भूलो मत, भूलो मत

कॉम्रेड्स,

शुरुआत से ही हमारे बैंक में एआयबीईए के बैनर तले महाबैंक के कर्मचारी संगठित हुए थे और इसलिए, तब से आजतक एआयबीईए बैंक में बहुमत में है। 1966 में पहली बार एआयबीईए द्वारा उद्योग के अनुसार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे लोकप्रिय रूप से पहले द्विदलीय समझौते के रूप में जाना जाता है। यह बैंकिंग उद्योग में द्विदलीयता की शुरुआत थी, जिसका पालन हमारे बैंक में भी किया गया। सेवा शर्तों और कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं से संबंधित सभी मुद्दों पर बैंक प्रबंधन मेमोरँडम ऑफ अंडरस्टँडिंग/ सेटलमेंट पर हस्ताक्षर करता था। इस अवधि के दौरान बैंक द्वारा यूनियनों को मुंबई, पुणे और नागपुर में कार्यालय स्थान प्रदान किया गया था ।

वर्ष 1981 में एआयबीईए से संबद्ध तीनों यूनियनें एक साथ आईं और फेडरेशन यानी ऑल इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉइज फेडरेशन का गठन किया गया । महाराष्ट्र राज्य के भीतर बैंक के तेजी से विस्तार को देखते हुए AIBOMEF नेतृत्व ने सोलापुर मराठवाड़ा के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज युनियन औरंगाबाद, नासिक-खानदेश के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज युनियन नासिक, पश्चिमी महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज युनियन, कोल्हापुर के अलग इकाई बनाने का सचेत निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, उन इकाइयों के गठन के बाद, बैंक ने उन संबंधित इकाइयों के क्षेत्र एवं मुख्यालय के बैंक परिसर में यूनियन कार्यालय के लिए स्थान प्रदान किया ।

जैसे ही बैंक ने महाराष्ट्र राज्य की सीमाओं से परे विस्तार किया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज युनियन मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज युनियन कोलकाता का गठन किया गया। इस विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज युनियन गुजरात और बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज युनियन आंध्र प्रदेश बनाकर आगे बढ़ाया गया ।

सात दशकों की अवधि के दौरान कई अवसरों पर औद्योगिक संबंध तनावपूर्ण रहे। संबंध विच्छेद कर दिए गए लेकिन अंततः दोनों पक्ष शांत हो जाते थे और उन सभी विवादास्पद मुद्दों पर मतभेदों को सुलझाने के लिए बातचीत की मेज पर आ जाते थे ताकि समझ विकसित हो सके और सामान्य स्थिति और शांति आ सके। किसी भी समय एक-दूसरे की मंशा पर शक नहीं किया गया।

इस अवधि के दौरान बैंक कई अवसरों पर अशांति और चुनौतीपूर्ण स्थिति से गुजरी । 1992-93 में प्रुडेन्शियल मानदंडों और नए लेखा मानकों के लागू होने के परिणामस्वरूप बैंक ने घाटे को बुक किया था। उस समय चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर और कार्यकारी निदेशक का पद रिक्त था। उस समय यूनियन ने बागडोर अपने हाथ में ले ली और सभी यूनियनों को साथ लेकर आगे बढ़ी और इस तरह बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबसे पहले संकट से बहार निकल पायी ।

एक बार फिर संकट 2017-18 में दुबारा आया जब तत्कालीन आरबीआई गवर्नर के कहने पर एसेट क्वालिटी इन्स्पेक्शन के परिणामस्वरूप बैंक ने भारी नुकसान दर्ज किया था । सभी यूनियनें एक साथ आईं और आगे बढ़ीं और इस प्रकार एक बार फिर यह बैंक ऑफ महाराष्ट्र थी जो सबसे पहले नुकसान से लाभ कमाने वाले बैंक में बदल गयी और सबसे पहले आरबीआई द्वारा लगाए गए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई प्रतिबंधों से बाहर आयी । एक समय मैनेजिंग डायरेक्टर

एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और अंचल प्रबंधक पुणे सिटी जोन को बिना किसी गलती के सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। मीडिया द्वारा खराब प्रचार किए जाने के बाद से बैंक पर भगदड़ मच गई थी। उस वक्त यूनियन फौरन हरकत में आ गई और 24 घंटे के भीतर मीडिया को यू टर्न लेना पड़ा। सभी यूनियनों ने एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और इस प्रकार एक सप्ताह की अवधि के भीतर स्थिति को नियंत्रण में लाया गया और उसके बाद बैंक संकट से उबर सकी ।

संघटन के रूप में हम तत्कालीन चेयरमैन श्री एस.सी. बसु, श्री नरेंद्र सिंह के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने में हमेशा आगे रहे और अनाचार, दुष्कर्म, भ्रष्टाचार और घोटालों का लगातार विरोध करते रहे । एक संघटन के रूप में हमें लगता है कि बैंक, बैंकिंग और सभी राष्ट्रों के हितों की रक्षा के लिए हमारे पास प्रहरी की भूमिका है और वर्तमान प्रबंधन हमारी इस भूमिका से विमुख है और बैंक के निदेशक मंडल में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की कमी की स्थिति का लाभ उठा रहा है ।

शुरुआत में बैंक प्रबंधन ने भारतीय व्यापार संघ अधिनियम के प्रावधानों से परे जाकर बोर्ड द्वारा अनुमोदित आईआर नीति पेश की, जिसमें यूनियन के निर्वाचित प्रतिनिधियों को आईआर फोरम में भाग लेने से रोक दिया गया, इस बहाने के साथ कि वे सेवानिवृत हैं। इसके बाद कर्मचारियों से संबंधित सभी मुद्दों पर द्विदलीयता को बंद कर दिया गया, जिस पर तब तक बैंक प्रबंधन समझौता कर रहा था और अब बैंक प्रबंधन उन कार्यालयों से यूनियनों को बलपूर्वक बेदखल कर रहा है, जिन में वे कई दशकों से कार्य कर रहे हैं, इस बहाने के साथ कि बैंक को जगह की जरूरत है .

वह दौर था जब बैंक ऑफ महाराष्ट्र के विलय और निजीकरण के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था लेकिन हमें लगता है कि इस समय तक हम विलय और निजीकरण दोनों की संभावित घटनाओं से बचने में सफल हो सके हैं। इसके बाद कोरोना की मेडिकल इमरजेंसी हुई जब हम सब अपनी-अपनी जान बचाने में लगे थे और इस तरह हमने औद्योगिक संबंधों के मुद्दों को प्राथमिकता नहीं दी लेकिन हमारे शांत और संयम को प्रबंधन द्वारा कमजोरी के रूप में गलत समझा गया।

इस दरम्यान प्रबंधन ने कर्मचारियों को विभिन्न आर्थिक लाभों का विस्तार किया, इस प्रकार उन्हें आकर्षित करने के लिए और इस प्रकार यूनियनों को उनकी सदस्यता से अलग करने के लिए, लेकिन सदस्यता की निस्संदेह वफादारी के लिए धन्यवाद। इसके बाद प्रबंधन ने अवार्ड स्टाफ कर्मचारियों के मन में अस्थिरता, अनिश्चितता और भय पैदा करने के लिए विशेष सहायक और सब स्टाफ कर्मचारियों सहित लिपिकों के प्रशासनिक तबादलों का सहारा लिया। प्रबंधन पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं कराकर और तथाकथित जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करके कर्मचारियों को और प्रताड़ित कर रहा है, लेकिन ऊपर से हाथ मरोड़ने की रणनीति के बावजूद सदस्य संघटनो के साथ खड़े रहे और इस प्रकार हम प्रबंधन की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ाई को उठाने में सक्षम रहे ।

उपरोक्त पृष्ठभूमि पर यूनाइटेड फोरम ऑफ महाबैंक यूनियनों ने आंदोलन को पुनर्जीवित करने और अपनी मांगों को पूरी ताकत और नए जोश के साथ आगे बढ़ाने का फैसला किया है। महाबैंक यूनियनों का यूनाइटेड फोरम एक दो दिनों में आंदोलन कार्यक्रम के साथ सामने आएगा।

इस बीच, ऑल इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज फेडरेशन कोर कमेटी ने यूनियन कार्यालय के मुद्दे पर आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। यह कार्यक्रम बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज युनियन औरंगाबाद, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज असोसिएशन नागपुर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज युनियन पुणे और बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज युनियन मुंबई के महाराष्ट्र के नियंत्रण वाले क्षेत्रों, अर्थात् उत्तर मुंबई, दक्षिण मुंबई, ठाणे और रायगढ़ क्षेत्र के अंचलों की सभी शाखाओं में लागू किया जाएगा।

आंदोलन कार्यक्रम

- **5 जनवरी 2023- विरोध दिवस-** इस दिन सदस्य काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे ।
- **12 जनवरी 2023-**उन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले जोनल मैनेजर के सामने **जन प्रतिनियुक्ति**, और अंत में कार्यालीन समय के बाद प्रदर्शन।
- **16 जनवरी 2023** - उन कमान क्षेत्रों के अंतर्गत सदस्य द्वारा **विरोध हड़ताल**।

कॉम्रेड्स, भारतीय संविधान ने हमें बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी दी है, संघटन बनाने का अधिकार दिया है। भारतीय संविधान ने हमें व्यक्त करने के लिए शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार दिया है और अंत में संविधान का अनुच्छेद 43A प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान करता है। इस के साथ भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम, साथ ही औद्योगिक विवाद अधिनियम भी हमें अधिकार, प्रतिरक्षा और विशेषाधिकार प्रदान करता है, जिसे वर्तमान प्रबंधन हमसे नहीं छीन सकता है।

यह आंदोलन प्रबंधन के संज्ञान में यह लाने के लिए है कि वे अपनी सीमा में रहकर काम करें। हम अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन पर हैं। हम देश के कानून के प्रावधानों का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे और शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी मांगों को आगे बढ़ाएंगे।

निश्चिंत रहें, हम सत्य पर आधारित सिद्धांतों पर हैं जिन्हें परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता।

अभिवादन के साथ।

आपका विश्वासी,

देविदास तुळजापूरकर
जनरल सेक्रेटरी